की जाती है कि वह 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं में प्रति सेक्शन 25 छात्र नामांकित करें।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया अनुदान संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शिक्षा विभाग

व्यावसायिक शिक्षा प्रभाग

शीर्षक:- माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया गया अनुदान)

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आन्ध्र प्रदेश	640.58	327.45	--
2.	अरूणाचल प्रदेश	--	--	--
3.	असम	291.54	164.42	108.52
4.	बिहार	408.51	157.87	415.39
5.	गोआ	56.93	100.42	115.04
6.	गुजरात	781.73	--	--
7.	हरियाणा	228.18	379.14	621.85
8.	हिमाचल प्रदेश	--	--	--
9.	जम्मू और कश्मीर	22.55	--	--
10.	कर्नाटक	1012.69	729.55	328.32
11.	केरल	352.40	885.23	929.35
12.	मध्य प्रदेश	--	20.80	--
13.	महाराष्ट्र	2035.74	2449.69	3134.44
14.	मणिपुर	7.40	40.24	35.24
15.	मेघालय	--	--	13.67
16.	मिजोरम	21.92	--	8.80
17.	नागालैंड	1.40	--	--
18.	उड़ीसा	650.00	102.20	--
19.	पंजाब	253.74	265.02	434.53
20.	राजस्थान	385.19	556.54	--
21.	सिक्किम	7.15	--	--
22.	तमिलनाडु	700.16	706.55	--
23.	त्रिपुरा	4.12	--	--
24.	उत्तर प्रदेश	258.42	265.37	502.40
25.	पश्चिम बंगाल	--	--	--
26.	अण्डमान और निकोबार	--	--	--
27.	चंडीगढ	22.77	23.94	26.86
28.	दादरा और नगर हवेली	2.79	--	--
29.	दमन और दीव	3.09	2.66	5.06
30.	दिल्ली	--	105.00	50.23
31.	लक्ष्यद्वीप	--	--	--
32.	पांडिचेरी	17.44	16.26	14.06
	कुल योग	8166.44	7298.02	6745.09

कोल इंडिया लि० के अन्तर्गत कंपनियों के अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के मामले

119. श्री दिलीप सिंह जुदेव: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30.10.1995 की स्थिति के अनुसार, कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों में कितने-कितने अधिकारी कार्यरत हैं एवं किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरण लंबित हैं;

(ख) इन अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण लंबित रहने के बावजूद, किन अधिकारियों को प्रत्येक कम्पनी में पदोन्नति दे दी गई है;

(ग) क्या इस तरह पदोन्नति दिया जाना नियमों के विपरीत है; और

(घ) यदि हां, तो नियम विरुद्ध पदोन्नति दिए जाने के आदेश पारित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) 30.11.95 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि० (को.इं.लि.) और इसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत 276 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले थे।

(ख) को.इं.लि. की सहायक कंपनियों में 17 अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया था, यद्यपि उनके विरुद्ध मामले लंबित पड़े थे।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित 17 अधिकारियों को जिन्हें पदोन्नति दी गई है, यह पदोन्नति नियमों के विरुद्ध नहीं है। कोल इंडिया लि० के संगत

नियमों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि ऐसा अधिकारी जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई/न्यायिक कार्रवाई का परिसमापन 2 वर्ष की अवधि तक भी नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में उससे कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख से उक्त अवधि के बाद उस अधिकारी को तदर्थ आधार पर पदोन्नति दी जा सकती है। ऐसे अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नति दी गई है, जो कि इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

(च) उपरोक्त (ग) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

Implementation of Prime inister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme

120. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to refer to answer to Starred Question No. 44 given in the Rajya Sabha on the 29th February, 1996, and state the ratio of financial assistance shared by the Centre and the States for implementing the Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATES WARLU): The component-wise details are given in the annexed statement

Statement

s. No.		Component	Funds Sharing Centre: State
A.	(a)	Basic physical amenities under EIUS	100% State
	(b)	Basic physical amenities to urban poor living in slums in permanent settlement areas.	60:40
	(ii)	Basic physical amenities under PM's IUPEP on whole town basis utilities like water supply, low cost sanitation, garbage and solid waste disposal with special focus on urban poor including small construction activities in urban poor localities (like roads, pavements, drainage, community baths/latrines and small community assets etc.)	60:4060
B.	(i)	Self employment Generation	60:40
	(ii)	Skill development training (Rs. 1000/per trainee P.M.)	100% Centre
	(iii)	Shelter upgradation including on site infrastructure subsidy of Rs. 2500/- per unit to urban poor who holds clear land title.	60:40
C.		Basic special amenities per capita cost of Rs. 100 proposed.	60:40
D.	(i)	Multi-purpose Community Kendras at suitable cost for 100 families (approx.)	50:50
	(ii)	Revolving funds for Thrifs & Credit Societies.	100% Centre
	(iii)	Community organisation support to NGOs/CBOs. (iv) Strengthening of ULBs including bench mark survey and project facilities.	100% Centre
	(v)	Training of elected representatives, functionaries of ULBs and community workers.	100% Centre